सत्यमेव जस्ते

आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015

GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136

E-Mail: commrappl1-cexamd@nic.in

Website: www.cqstappealahmedabad.gov.in



By Regd. Post

DIN No.: 20221264SW000000A792

	•						
(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/1772/2022-APPEAL /5677-81					
(ख)	अपील आदेश संख्या और दिनांक / Order-In-Appeal No. and Date	AHM-EXCUS-003-APP-072/2022-23 and 08.12.2022					
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री अखिलेश कुमार, आयुक्त (अपील) Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals)					
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of issue	09.12.2022					
(롱)	Arising out of Order-In-Original No. AC/S.R./11/ST/Kadi/2021-22 dt. 28.02.2022 passed by the Assistant Commissioner, CGST & CE, Division-Kadi, Gandhinagar Commissionerate						
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant	M/s Rudrani Enterprise (PAN-AVOPG9016H), Crystal Plaza, C/130 Kadi Kalol Road, Kadi, Mehsana, Gujarat					

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोश अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

Revision application to Government of India:

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूवोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए:-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid: -

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार मे हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

•In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपंत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गतः-Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2ndfloor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of RS-1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of grossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public

sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है ती प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संषोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

- (1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशिय;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा ' लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना मेंए अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

अपीलिय आदेश / ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s Rudrani Enterprise, Crystal Plaza – C/130, Kadi Kalol Road, Dist.Mehsana, Gujarat (hereinafter referred to as the appellant) against Order in Original No. AC/SR/11/ST/KADI/2021-22 dated 28.02.2022 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division - Kadi, Commissionerate: Gandhinagar [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

- 2. Briefly stated, the facts of the case is that the appellant were engaged in providing 'Manpower Recruitment/Supply Agency Service' and were holding Service Tax Registration No. AVOPG9016HSD001 for the same. The data pertaining to 'Sales/Gross Receipts from Services (Value from ITR); the Total Amount paid/Credited under section 194C, 194H, 1941, 194J' of the Income Tax Act and 'Gross Value of Services Provided' was provided by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the F.Y. 2014-15, and on its analysis, it was noticed that the appellant had shown less amount of the 'Gross Value of Services Provided' in their Service Tax (ST-3) Returns filed with Service Tax Department compared to those filed with the Income Tax Department. To explain the discrepancies, the appellant were requested vide letters/e-mails to provide documents viz. Balance Sheet, Profit & Loss Account, Income Tax Returns, Form 26AS, Service Income and Service Tax Ledger and Service Tax (ST-3) Returns for the F.Y. 2014-15. However, the appellant did not respond.
- 2.1 Accordingly, the service tax liability of the appellant was determined for the F.Y. 2014-15 based on the maximum amount of difference between (i) Value of Services declared in ITR filed by the appellant & Value of Services provided as per Service Tax Returns and (ii) Value of "Total Amount paid/credited under Sections 194C, 194H, 1941, 194J' of the Income tax Act & Value of Services provided as per Service Tax Returns.

The details of quantification of demand are as per the Table below:

	•	<u>rable</u>			(Amount in Rs.)			
Financ ial Year	Value of services declared in ITR	Value of total ramount paid/credited under 194C, 194H, 194I, 194J	Value of services provided as per service tax returns	Highest Differe nce	Basic Service Tax@ 12%	Ed. Cess @ 2%	S & H Ed. Cess @·1%	Total Service Tax
2014- 151 ta Ha	0/-	20281/-	0/-	20281/-	2434/-	49/-	24/-	2507/-

- 2.1. The appellant was issued a Show Cause Notice No. IV/16-15/TPI/PI/Batch 3C/2018-19/Gr.IV dated 25.06.2020 (in short SCN) for demand and recovery of Service Tax amounting to Rs.2507/- under proviso to sub-section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 read with Section 68 of the Finance Act, 1994 read with relaxation of provisions of Section 6 of Chapter V of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (No 2 of 2020) promulgated on 30.03.2020 by invoking extended period of limitation along with interest under Section 75 of the Act. The SCN also proposed imposition of penalty under Sections 77 and 78 of the Finance Act, 1994.
- 3. The SCN was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order wherein:
 - (i) The demand of service tax amounting to Rs. 2,507/- was confirmed under proviso to sub-section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 read with Section 68 of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.
 - (ii) Penalty amounting to Rs. 2,507/- was imposed under Section 78 of the Finance Act, 1994
 - (iii) Penalty amounting to Rs.10,000/- was imposed under Section 77 of the Finance Act, 1994.
- 4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant have filed the present appeal on following grounds:
 - The Service Tax confirmd against the appellant has been paid by M/s Hitachi Air Conditioning India Limited under Reverse Charge Mechanism. They have also attached copy of Challan evidencing payment of duty.
 - As the demand has already been paid as per above, they also refute the demand of imposition of penalty imposed under Section 78 and 77 of the Finance Act, 1994 (FA, 1994).
- 5. Personal Hearing in the case was held on 30.11.2022, Shri Hiren R.Patel, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellant for the hearing. The appellant re-iterated the submissions made in application for condonation of delay.



- I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum, submissions made during personal hearing and material available on records. It is observed from the records that the present appeal was filed by the appellant on 07.06.2022 against the impugned order dated 28.02.2022, which the appellant have claimed to have received on 16.03.2022. Therefore, the period of two months for filing the appeal before the Commissioner (Appeals) ended on 16.05.2022 and this appeal was filed on 07.06.2022 i.e after 23 days of expiry of the period of 2 months.
- 7. In terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, an appeal before the Commissioner (Appeals) is to be filed within a period of two months from the receipt of the order being appealed. Further, the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994 allows the Commissioner (Appeals) to condone delay and allow a further period of one month, beyond the two month allowed for filing of appeal in terms of Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.
- It is observed that the appellant, who is registered with Service Tax 8. department, have in the instant case in an attempt to explain the said delay of 23 days in filing the appeal, attributed the delay towards "documents were not in the process", which I do not find as a plausible and cogent reason for condoning the period of delay and exercising the discretion vested upon me vide the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.
- 9. In view of the facts discussed herein above, without delving into the merits of the case, I reject the appeal filed by the appellant on the grounds of limitation.

अपीलकर्ताद्वारादर्जकीगईअपीलकानिपटाराउपरोक्ततरीकेसेकियाजाताहै। 10. The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

> Akhilesh Kumar) Commissioner (Appeals)

Date: 08th December, 2022

Attested:

(Somnath Chaudhary) Superintendent (Appeals), CGST, Ahmedabad.



BY RPAD / SPEED POST

To

M/s Rudrani Enterprise, Crystal Plaza, C/130, Kadi Kalol Road, Kadi, Dist.Mehsana, Gujarat.

Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner, CGST, Commissionerate Gandhinagar.
- 3. The Assistant Commissioner, Central GST Division Kadi, Commissionerate : Gandhinagar.
- 4. The Assistant Commissioner (System), CGST, Appeals, Ahmedabad. (for uploading the OIA)
- 5. Guard File.
 - 6. P.A. File.



